भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2639

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कृषि नीति

2639. श्री तीरथ सिंह रावतः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों हेतु कोई पृथक कृषि नीति/कार्य योजना बनाई है या ऐसी कोई योजना बनाने का विचार है जो कि मैदानी जिलों से भौगोलिक रूप से भिन्न है और तराई क्षेत्रों की तरह वहां सिंचांई और कृषि सुविधाएं नहीं हैं तथा जहां कृषि पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): जी, नहीं। चूंकि कृषि एक राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार, कृषि में सुधार लाने एवं उत्तराखंड सहित देश में किसानों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। केन्द्र एवं राज्यों के बीच शेयरिंग पद्धति पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 3 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड सहित) के लिए 90:10 अनुपात तथा शेष राज्यों के लिए 60:40 अनुपात में दी जाती है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता मांग-आधारित है तथा राज्य सरकारों को ये निधियां उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण एवं पिछली निर्मुक्तियों की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर दी जाती हैं। स्कीमों की सूची **अनुबंध** पर दी गई है।

लो.स.अता.प्र.सं. 2639

अनुबंध

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	**स्कीम का नाम**
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
2.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल
3.	फसल अपशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
4.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
5.	पीएम-किसान (आय सहायता स्कीम)
6.	पीएम-किशन - पेंशन
	हरित क्रांति
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- रफ्तार
	कृषोन्नति योजना
8.	समेकित बागवानी विकास मिशन
	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
9.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
11.	वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
12.	परम्परागत कृषि विकास योजना
13.	कृषि-वानिकी उप-मिशन
14.	पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन
15.	राष्ट्रीय कृषि ई-गवर्नेंस योजना
16.	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन
17.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन
18.	पादप संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन
19.	समेकित कृषि सहकारिता स्कीम
20.	समेकित कृषि विपणन स्कीम
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
21.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - तिलहन एवं ऑयल पाम
22.	समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी स्कीम
23.	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
24.	राष्ट्रीय कृषि मंडी

*****